that we have the best use for it. Today the use of oil is not at all regulated. We are not in a position to get the best realisation. International fluctuation in prices causes such wide losses to us in forcign exchange, and we are not using oil in the most....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

I was waiting for you to finish the sentence, but you did not.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Target for Rural Houses Under IAY

*82. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what is the target for construction of rural houses under the Indira Awas Yojana during the current financial year, State-wise;

(b) whether Government are satisfied with the pace of implementation to achieve the target; and

(c) if not, what measures are contemplated to accelerate the pace?

THE MINISTER OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) A Statement is laid on the Table of the House. (*See* below).

(b) Pace of construction under Indira Awas Yojana is by and large satisfactory.

(c) the progress of the scheme is being vigorously monitored.

Statement

Targets fixed under Indira Awas Yojana during 1996-97 for different States/UTs are as under

State/UT	Target
Andhra Pradesh	84640
Arunachal Pradesh	631
Assam	29197
Bihar	151453
Goa	1736
Gujarat	33633
Haryana	6983
Himachal Pradesh	2165
Jammu & Kashmir	5347
Karnataka	53181
Kerala	18554
Madhya Pradesh	147902
Maharashtra	81120
Manipur	808
Meghalaya	946
Mizoram	398
Nagaland	1014
Orissa	62248
Punjab	4966
Rajasthan	50325
Sikkim	369
Tamil Nadu	71598
Tripura	1051
Uttar Pradesh	241251
West Bengal	70979
A&N Islands	337
D&N Haveli	278
Daman & Diu	120
Lakshadweep	0
Pondicherry	330
TOTAL	1123560

Import of Gas from Oman and Iran

*84. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the feasibility study of importing gas from Oman and Iran to be used in power stations in the country;

(b) if so, whether Government have decided to supply this imported gas to Pipavav Power Project in Gujarat; and

(c) if not, how Government propose to supply fuel to the Pipavav Power Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU):

(a) The Oman Oil Company (OOC) took up the feasibility study for the Oman-India gas pipeline project but is yet to complete the study. A joint Working Group has been formed by GAIL and OOC to expedite the feasibility study. The feasibility study for the Iran-India pipeline project can be progressed after the consent of the Government of Pakistan is received for the pipeline route survey.

(b) Does not arise.

(c) the Pipavav Power Project can avail of alternative fuels such as coal, fuel oil and naphtha subject to the prevailing Government policy and techno-economic feasibility.

नीति खण्ड, सेक्टर-3, इन्दिरापुरम योजना में उपलब्ध सुविधाएं

*86. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री 12 सितम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3943 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन्दिरा पुरम योजना के अन्तर्गत सभी सुविधाओं से युक्त पूर्णतया विकसित फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को दे दिया है;

(ख) क्या नीति खण्ड, सेक्टर-3 में टाइप "ए" और "बी" के एच०आई०जी० डुपलेक्स फ्लैटों का कब्जा भी आवंटियों को दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब और ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के पश्चात कब तक इनका कब्जा दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन्दिरापुरम योजना के तहत निम्नलिखित पाकेटों के रिहायशी मकानों, जिनमें सुविधाएं मुहैया करा दी गयी हैं, के आवंटियों को नियमानुसार कब्जा दिया जा रहा है:—

पाकेट सं०	श्रेणी	मकानों की संख्या
शक्ति खण्ड—1—	एल आई जी	टाइप I—540 टाइप—II—744
ज्ञान खण्ड—4—	एच आई जी (एक मंजिला)	—030
	एम आई जी (चार मंजिले)	—396

(ख) और (ग) नीति खण्ड-3 में "ए" और "बी" टाइप के कुल 400 एच०आई०जी० डुप्लेक्स मकानों में से 300 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बकाया देय राशि का पूरा भुगतान करने जैसी शर्तों को पूरा करने के पश्चात आवंटियों द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध करने पर जलापूर्ति, मलजल निकासी और विद्युत जैसी आवश्यक सेवा सुविधाओं सहित नियमानुसार इन मकानों का कब्जा दिया जा सकता है।

टाइप "बी" के शेष 70 मकानों का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा काम छोड़ देने तथा मामले पर पंच निर्णय होने तक रुका पड़ा है।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंकों के मध्य अनुपात

*88. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री शिव चरण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और सहबद्ध सेवाओं इत्यादि सहित विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

906/25-27